CLASSMATE
Date 16-05-2020
Page (1)

USHA KUMARI
Guest Asstt. Professor,
Dept. of Economics,
Vaishali Mahila College, Hajipur

Part - I
Paper - II

स्फीति-नियंत्रण
(Control of Inflation)

द्रव्य मूल्य या सामान्य कीमत-स्तर में एकाएक परिवर्तन होने से सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाओं को धक्का लगता है और वे अनिश्चित हो जाती हैं, इसलिए कीमतों के स्थायीकरण की आवश्यकता होती है। कीमतों के स्थायीकरण का अर्थ यह नहीं है कि उनको पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जाय। इस प्रकार की व्यवस्था न तो संभव है और न ही उसकी आवश्यकता है। क्यों कि कीमतों में थोड़े-थोड़े समय के उतार-चढ़ाव को बिलकुल रोका नहीं जा सकता, चाहे वे कुछ थोड़ी-सी वस्तुओं की कीमतें हों या सामान्य कीमत-स्तर। सामान्य कीमत-स्तर में अत्यधिक और एकाएक आने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से निम्न दो प्रणालियों को अपनाया जाता है :

(1) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)
(2) मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

(1) राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

राजकोषीय नीति का तात्पर्य वित्त प्रबंधन के कुछ खास उपायों से है जिसे सरकार द्वारा स्फीति की स्थिति को रोकने अथवा नियंत्रित करने के लिए अपनाया जाता है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार की आय के स्रोतों (Revenue) और उसके व्यय के सिद्धांतों का सही उपयोग है। कीन्स के अनुसार जब सरकार करों की दरों में परिवर्तन

जाती है तो इससे समग्र मांग (aggregate demand) और वित्तीय कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। वस्तुतः व्यापार-चक्र के दौरान अर्थव्यवस्था के स्थीरीकरण के लिए राजकोषीय नीतियाँ अपनायी जाती हैं।

(Instruments of Fiscal Policy) राजकोषीय नीति के साधन :

राजकोषीय नीति के साधनों को मुख्यतः दो श्रेणियों में बाँटा गया है —

(a) सार्वजनिक व्यय (Government Expenditure) और
(b) सार्वजनिक व्यय का वित्त पोषण अर्थात् आय के साधन।
(Financing of Expenditure or Government Revenue)

(a) सार्वजनिक व्यय (Government Expenditure) :

सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक अधिकारियों – केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों – द्वारा किया जाने वाला व्यय है। सरकार अनेकों प्रकार के व्यय करती है। मुख्य हैं —

(i) लोक-निर्माण कार्यों, जैसे सड़क, बांध पुलों के निर्माण आदि कार्य पर व्यय करना (Expenditure on public works programme such as the construction of roads, dams, bridges etc.)।

(ii) शिक्षा एवं लोक कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय (Expenditure on education and public welfare programme)।

(iii) देश की सुरक्षा एवं निम्न और कानून को बनाये रखने पर व्यय (Expenditure on the defence of the country and the maintenance of law and order)।

(iv) देश के विभिन्न वर्गों को अनेकों प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करना अर्थात् व्यय करना (Expenditure on various types of subsidies)

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त वर्णित व्ययों में से किसी तक या सभी में परिवर्तन लाकर सरकार अतिरेक मांग (Excess demand, i.e., inflationary situation) अथवा मांग की कमी (Deficient demand, i.e., deflationary situation) की समस्या को सुधारने का प्रयत्न करती है।

(b) सार्वजनिक व्ययों का वित्त पोषण अर्थात् सार्वजनिक आय के साधन (Financing of Government Expenditure or sources of Government Revenue):

उपर्युक्त वर्णित सार्वजनिक व्ययों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सरकार को आय की आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न साधनों से जो आय प्राप्त करती है उसे सार्वजनिक आय अथवा लोक आगम (Public Revenue) कहते हैं। संकुचित अर्थ में सार्वजनिक आय से अभिप्राय केवल करों से प्राप्त मौद्रिक आय से है किन्तु व्यापक रूप में सार्वजनिक आय में सभी प्रकार की आय तथा प्राप्तियाँ आ जाती हैं। सार्वजनिक व्ययों के वित्त-पोषण के मुख्य यंत्रों के रूप में करारोपण (Taxation), सार्वजनिक ऋण (Public Debt) तथा राजकोषीय घाटा (Deficit Financing) को अपनाया जाता है। इन यंत्रों का उपयोग कर सरकार अतिरेक मांग (Excess demand) और मांग की कमी (Deficient demand) की समस्या को दूर करने का प्रयत्न करती है। ये यंत्र हैं:-

(i) कर (Tax):

सरकार जनता से अनिवार्य रूप से सार्वजनिक कार्यों के संचालन के लिए जो धन वसूलती है उसे कर कहते हैं। कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।—

(a) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) और

(b) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes)।

Scanned with CamScanner